जनपद बस्ती को पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना प्रदेश सरकार ने बना रखी है ।

इस क्षेत्र में रा-मैटीरियल पानी की तरह बह रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जैसे सीरा का उपयोग अभी तक करने का निश्चय प्रदेश सरकार ने नहीं किया जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषतः बस्ती, गोरखपुर, देवरियां जनपदों में गन्ने की मिलें बहुत अधिक हैं और लाखों टन सीरा पानी की तरह नदियों और नालों में बहा दिया जाता है। इस से प्रदेश और भारत सरकार को वित्तीय हानि भी हो रही है ।

ऐसी दशा में मैं माननीया प्रधान मंत्री एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि सीरा पर निर्भर जो उद्योग लगाये जा सकते हैं उन्हें खलीलाबाद में लगाया जाये और उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया जाये कि इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही करे जिससे खलीलाबाद और इस क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल सके ।

(x) Need to issue licence for setting up of Cooperative Sugar Mill in Puwayan district Shahjahanpur (U.P.).

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील का विशेष स्थान है। यह क्षेत्र गन्ना, धान व गेंहू का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। परन्तु इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है ।

अधिकारियों ने पुवायां क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल खोलने के लिये एक लायसेन्स देने के निमित्त केन्द्रीय सरकार को लिखा है। परन्तु दो वर्ष से भी अधिक बीत जाने पर वहां सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये लायसेन्स नहीं दिया गया है। इस से स्पष्ट है कि सरकार के पिछड़े जिलों में विशेष उद्योगीकरण की घोषित नीति का परिपालन नहीं हो रहा है। इस से संतुलित विकास की प्रक्रिया में बाधा पड़ रही है। मैंने संबंधित अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात की तो उन्होंने बताया कि पुवायां में सहकारी चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है परन्तु केन्द्रीय सरकार से अनुमति तक नहीं मिली है।

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि पुवायां (शहजहांपुर) में तुरन्त एक सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये लायसेन्स देने की कृपा करें।

(xi) Need for strictly implementing use of Hindi in Government offices.

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, एक और सरकार आश्वासन देने में कुशल है, दूसरी और उसकी सरकारी मशीनरी उन आश्वासनों का मजाक बनाने में संलग्न है। देश की भाषा हिन्दी को शनैः-शनैः बिना उसे किसी पर थोपें, राष्ट्र भाषा के स्थान पर आसीन करने के आश्वासन के बावजूद सरकारी संस्थानों में उस दिशा में हो रहे कार्यों का एक उदाहरण आज में सदन में रखना चाहता हूं।

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ बेंकट, वम्बई द्वारा सी० ए० आई० आइ० बी० की परीक्षाएं ली जाती हैं किन्तु इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को हिन्दी उपयोग करने की अनुमति नहीं है। उक्त संस्थान के सहायक, सचिव (परीक्षा) ने स्पष्ट शब्दों द्वारा एक पत्र में इस अनुमति के देने में अस्वीकृत प्रकट की है। मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में तो सरकार जांच करे ही साथ ही ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाये ताकि उस दिशा में निरंतर प्रगति का आभास हो सके।

(xii) Need for releasing more quota of foodgrains for Tripura.